



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236252
CG-DL-E-02062022-236252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]
No. 393]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2022/ज्येष्ठ 12, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2022/JYAISHTHA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

सं. 3/2022-सीमा शुल्क (सीबीडी)

सा.का.नि. 414(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “साकारीन”, जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2925 11 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2019, जिसे दिनांक 19 जून, 2019, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि चीन जनवादी गणराज्य से भारत को सब्सिडी वाले मूल्य पर निर्यात किए गए साकारीन, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

और, जबकि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमा शुल्क (सीबीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 30 अगस्त, 2019 में सा.का.नि. 610(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से साकारीन पर काउंटरवेलिंग छ्यूटी लगाई गई थी;

और, जबकि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, इसकी प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 07/05/2022-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 17 मार्च, 2022, में प्रकाशित, ने जंच शुरू की है की थाइलैंड से इन सामानों के आयात द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से साकारीन के आयात पर काउंटरवेलिंग छ्यूटी के कथित उल्लंघन के संबंध में, विरोधी परिधि जांच शुरू की है;

और, जबकि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने थाईलैंड से साकारीन के आयात द्वारा व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में खुद को संतुष्ट किया है, इस प्रकार, मौजूदा काउंटरवेलिंग ड्यूटी उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम करते हुए, और तदनुसार विषय के सभी आयातों पर अस्थायी मूल्यांकन की सिफारिश की है, यानी "सैकरीन", थाईलैंड से आयात किया गया था, जब तक कि उपर्युक्त उल्लंघन-विरोधी जांच पूरी नहीं हो जाती।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सीडीसेड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संब्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 26 के उप-नियम (4अ) के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्वोक्त सिफारिश पर विचार करने के बाद, एतद्वारा आदेश देती है कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त उल्लंघन-विरोधी जांच के परिणाम तक, थाईलैंड से भारत में साकारीन के सभी आयातों का अस्थायी मूल्यांकन तब तक किया जाएगा जब तक उक्त जांच का समापन नहीं हो जाता।

2. अस्थायी मूल्यांकन ऐसी सुरक्षा या गारंटी के अधीन हो सकता है, जैसा कि सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को कमी के भुगतान के लिए उपर्युक्त लगता है, यदि कोई हो, यदि कोई निश्चित काउंटरवेलिंग ड्यूटी पूर्वव्यापी रूप से लगाया जाता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर।

3. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त विरोधी परिशि जांच के पूरा होने के बाद काउंटरवेलिंग ड्यूटी की सिफारिश के मामले में, आयातक इस तरह के काउंटरवेलिंग ड्यूटी की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि थाईलैंड से साकारीन के भारत में सभी आयातों पर लगाया जाता है, उक्त जांच की शुरूआत की तारीख से।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/112/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2022

No. 3/2022-Customs (CVD)

G.S.R. 414(E).—Whereas, in the matter of “Saccharin” falling under tariff item 2925 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from China PR and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, *vide*, notification No. 6/18/2018-DGAD, dated the 19th June, 2019, had come to the conclusion that the Saccharin exported to India from China PR at subsidised value, thus, resulting in material injury to the domestic industry;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed a countervailing duty on the Saccharin, *vide*, notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2019-Customs (CVD), dated the 30th August, 2019, published, *vide*, number G.S.R. 610(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th August, 2019;

And, whereas, the designated authority, *vide*, its initiation notification No. 07/05/2022-DGTR, dated the 17th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th March, 2022, has initiated anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of countervailing duty on imports of Saccharin from China PR by imports of these goods from Thailand;

And, whereas, the designated authority has satisfied itself regarding the change in pattern of trade by imports of Saccharin from Thailand, thus, undermining the remedial effect of the existing countervailing duty measures, and has accordingly recommended provisional assessment on all imports of the “Saccharin”, imported from Thailand, till the completion of the abovementioned anti-circumvention investigation.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with sub-rule (4A) of rule 26 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that, pending the outcome of the abovementioned anti-circumvention investigation by the designated authority, all imports of the Saccharin from Thailand into India shall be subjected to provisional assessment till the completion of the said investigation.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive countervailing duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of countervailing duty after completion of the abovementioned anti-circumvention investigation by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such countervailing duty as is imposed on all the imports of the Saccharin from Thailand into India, from the date of initiation of the said investigation.

[F. No. CBIC-190354/112/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.